देहरादून (उत्तराखण्ड)
मंगलवार 01.04.2025
समय 1305

मुख्य समाचार :–

- प्रदेश में नई आबकारी नीति के तहत राजस्व संग्रह में बड़ा इजाफा, वर्ष 2024–25 में आबकारी विभाग को चार हजार तीन सौ साठ करोड़ का राजस्व मिला।
- केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना आज से लागू हो रही है।
- राज्य सरकार ने चंपावत जिले की सड़क व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए करीब 43 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी।
- उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के गेट पर्यटकों के लिए खोले गए।

राजस्व संग्रह बढोतरी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लागू की गई नई आबकारी नीति ने राजस्व संग्रह में बड़ा इजाफा किया है। वर्ष 2024–25 में आबकारी विभाग को चार हजार तीन सौ साठ करोड़ का राजस्व मिला, जो 2021–22 की तुलना में ग्यारह सौ करोड़ रुपए अधिक है।

सरकार का दावा है कि राजस्व में बढोतरी की यह सफलता अवैध शराब पर सख्त नियंत्रण और शराब उद्योग में निवेश बढ़ाने के कारण मिली है। नई नीति के तहत राज्य में बनने वाले उद्योगों में 80 प्रतिशत प्राथमिकता स्थानीय लोगों को दी जा रही है, जिससे रोजगार के मौके बढ़े हैं। सप्लाई चेन, परिवहन और अन्य सेवाओं से भी स्थानीय लोगों को फायदा मिला है।

उत्तराखंड अब उपभोक्ता से उत्पादक और निर्यातक राज्य की ओर बढ़ रहा है। ऊधम सिंह नगर में एथेनॉल के दो नए प्लांट लग रहे हैं, जो औद्योगिक विकास और युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलेंगे। हरिद्वार, चंपावत, बागेश्वर जैसे जिलों में भी डिस्टलरी, वाइनरी, ब्रूवरी और बॉटलिंग प्लांट के जरिए आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं।

राज्य में बनी शराब की करीब 12 लाख पेटियाँ अमेरिका, इटली, अफ्रीका और घाना जैसे देशों को निर्यात की जा रही हैं। इससे राज्य को विदेशी मुद्रा मिल रही है और ''मेड इन उत्तराखंड'' उत्पादों की पहचान वैश्विक स्तर पर मजबूत हुई है।

सरकार का कहना है कि आबकारी विभाग ने पारदर्शी नियमों और आसान लाइसेंसिंग प्रक्रिया से उद्योगों को बढ़ावा दिया है। साथ ही अवैध शराब पर सख्ती से रोक लगाकर अधिक राजस्व, व्यापक रोजगार और सतत आर्थिक विकास का रास्ता तैयार किया है।

यूपीएस

केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना–यूपीएस आज से लागू हो रही है। केंद्र सरकार ने यूपीएस को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने हाल ही में यूपीएस के संचालन के लिए नियम अधिसूचित किए थे। ये नियम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के तीन समूहों से संबंधित हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

धनराशि जारी

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के तहत उत्तराखंड को बीस करोड़ 66 लाख रुपए की धनराशि जारी की है। इस बजट से राज्य के सरकारी विद्यालयों की रसोइयों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, ताकि बच्चों को ताजा और पौष्टिक मध्याह्न भोजन मिल सके।

विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि इस धनराशि से प्रदेश के 292 विद्यालयों में नए किचन कम स्टोर बनाए जाएंगे। साथ ही साढ़े आठ हजार से अधिक विद्यालयों की क्षतिग्रस्त रसोइयों की मरम्मत की जाएगी और 772 विद्यालयों में रसोई से जुड़े उपकरण बदले जाएंगे। उन्होंने कहा कि लगभग चार वर्ष बाद इस योजना के लिए केंद्र से बजट मिला है, जिससे स्कूलों की रसोइयों में व्यापक सुधार हो सकेगा।

डॉ. रावत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान के तहत इस साल प्रदेश में छह ईट राइट किचन भी स्थापित किए जाएंगे। ये किचन पूरी तरह स्वच्छ और हाईजिनिक होंगे, जहां बच्चों को पौष्टिक ईट राइट थाली परोसी जाएगी। इसका प्रस्ताव जल्द ही केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

मंजूरी

प्रदेश सरकार ने चंपावत जिले की सड़क व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 43 करोड़ ग्यारह लाख रुपये की स्वीकृति दी है। यह मंजूरी केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि योजना के तहत दी गई है। परियोजना के तहत काठगोदाम से पंचेश्वर तक के मोटर मार्ग के 36 किलोमीटर लंबे हिस्से को सुधारा जाएगा।

प्रमुख जिलाधिकारी जयवर्धन शर्मा ने बताया कि यह मंजूरी वित्तीय वर्ष 2024–25 के निर्धारित मानकों और दिशा–निर्देशों के अनुसार दी गई है। इस परियोजना से चंपावत जिले में यातायात सुविधा बेहतर होगी। स्थानीय लोगों के साथ–साथ पर्यटकों को भी अच्छी सड़क सुविधा मिलेगी, जिससे क्षेत्र के आर्थिक और पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा।

गंगोत्री पार्क

उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के गेट आज पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। लगभग 2 हजार 390 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह पार्क हिम तेंदुए के प्राकृतिक घर के रूप में पहचान रखता है। हिम तेंदुए के अलावा यहां काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, नीली भेड़ या भरल, हिमालयन मोनाल आदि पाए जाते हैं। पार्क के रेंज अधिकारी ने कहा कि भूस्खलन और ग्लेशियर के कारण गंगोत्री–गोमुख ट्रैक पर मरम्मत कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस ट्रेक को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं।

गौरतलब है कि इस साल गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के लिए दो नए ट्रैक रूटों का भी शुभारम्भ हुआ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीते छह मार्च को अपने हर्षिल व मुखवा दौरे पर गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्र में चीन सीमा पर जादूंग से जनकताल व नीलापानी से मुलिंग–ला ट्रैक का शुभारंभ किया। इन दोनों ट्रैक पर मई से अक्टूबर तक ट्रैकर्स को ट्रैकिंग की अनुमति मिलने की उम्मीद है।

ग्रीन टैक्स

अब नैनीताल आने वाले पर्यटकों को ग्रीन टैक्स देना होगा। बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने यह नया नियम लागू किया है। यह टैक्स मुख्य रूप से वाहनों पर लागू होगा, जिससे नगर में प्रवेश करने वाले बाहरी वाहनों को निर्धारित शुल्क अदा करना होगा। नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल ने बताया पर्यटकों से करीब 150 रुपए ग्रीन टैक्स लेने की योजना बनाई जा रही है। जल्द ही विधिक राय लेने के बाद ग्रीन टैक्स लेने का काम शुरू हो जाएगा। शहर के नारायण नगर और भवाली, हल्द्वानी रोड क्षेत्र में ग्रीन टैक्स बूथ बनाया जाएगा।

नैनीताल अपनी प्राकृतिक सुंदरता, झीलों और हरे–भरे जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। हर साल हजारों पर्यटक यहां घूमने आते हैं। जिससे नगर की सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ जाता है और प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता है। खासकर, वीकेंड और छुट्टियों के दौरान यहां भीड़ बहुत बढ़ जाती है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका और जिला प्रशासन ने ग्रीन टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। यह टैक्स नैनीताल में प्रवेश करने के समय निर्धारित बैरियर पर लिया जाएगा। स्थानीय निवासियों और उत्तराखंड परिवहन की बसों को इससे छूट दी गई है।